प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 42 अंक – 2 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 09 – 16 जनवरी 2017 मूल्य पांच रूपए

# पहली ही बर्फबारी में चरमरायी सारी व्यवस्थाएं सरकार और प्रशासन की संवेदनशीलता पर उठे सवाल

**शिमला/बलदेव शर्मा**

वीरभद्र सिंह और उनके आश्रितों टीम लगातार दावे करती आ रही है कि कांग्रेस पुनः सत्तासीन होगी और वीरभद्र सिंह सातवीं बार प्रदेश के मुख्यमन्त्री बनेगे। राजनीति में ऐसे दावे किये जाना कोई नयी बात नही है। हर सत्तासीन पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व ऐसे दावे करता ही है। जो दल और उसका नेतृत्व सही मायनों में जनता के लिये काम करता है उस पर जनता भरोसा भी करती है। उसकी सत्ता में वापसी भी सुनिश्चित करती है। देश के कई राज्य इसके गवाह हैं। लेकिन हिमाचल में डा. परमार के बाद कोई भी मुख्यमन्त्री लगातार दो बार सत्ता में नही रह पाया है जबकि हर बार दावे सत्ता में वापसी के किये जाते रहे हैं। सत्ता में वापसी सरकार का काम और उसके नेतृत्व की छवि सुनिश्चित करती है। उसका प्रशासन जन समस्याओं के प्रति कितना संवेदनशील और जवाबदेह होकर काम करता है सत्ता की वापसी का सबसे बड़ा मानक प्रमाणित होता है। लेकिन इस बार राजधानी शिमला में ही जिस तरह से पहली ही बर्फबारी में सारी आवश्यक सेवाएं और व्यवस्थाएं चरमरा गयी उससे न केवल कांग्रेस पार्टी और स्वंय वीरभद्र सिंह के दावों का खोखलापन सामने आया है बल्कि सरकार और नेतृत्व की नीयत तक पर सवाल उठ खड़े हुए है।

शिमला प्रदेश की राजधानी है और बर्फबारी का जाना माना क्षेत्र है। यहां की बर्फबारी पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केन्द्र रहती है। शिमला सौंदर्यकरण पर एशियन विकास बैंक से 259 करोड़ का कर्ज लेकर खर्च किया जा रहा है। सौंदर्यकरण के नाम पर किये जा रहे विभिन्न कार्यो के लिये नियुक्त कन्सलटैन्टस पर ही 31.3.15 तक करीब 21 करोड़ खर्च किया जा चुका है। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन आज तक हमारे यह विशेषज्ञ सलाहकार और सरकार का पूरा तन्त्र यह नही सोच पाया है कि शहर में बिजली, पानी और टेलीफोन जैसी आवश्यक सेवाओं की लाईनों को अन्डर ग्राऊंड किया जाना चाहिये। हर बरसात और बर्फबारी में पेड़ टुटते और गिरते हैं तथा इन लाईनों पर गिरते है। लेकिन आज तक इसके स्थायी समाधान का रास्ता नही निकाला गया है।

इस बार की बर्फवारी में राजधानी समेत पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। राजधानी के अस्पतालों तक में बिजली गुल रही। बिजली न होने से पानी की सप्लाई बाधित रही। पहली बार है कि शहर में बर्फबारी के कारण करीब एक दर्जन मौतें हो गयी। नगर निगम प्रशासन ने कुछ आवश्यक रास्ते तो साफ कर दिये लेकिन उसके पास नियमित लेवर कम होने से सभी जगह के रास्ते तो साफ नही हो पाये। यदि एसपी शिमला ने शहर में आने वाले पर्यटकों की गाड़ियों को बैरियर पर ही रैगुलेट न किया होता तो भारी जानमाल का नुकसान हो सकता था। बिजली और पानी न होने से मालरोड़ तक के रेस्तरां बन्द रहे। बिजली न होने से बैंको में ट्रांजैक्शन तक नही हो पाये। ग्राहकों को न तो बैंको से और न ही एटीएम से पैसा मिल पाया। पूरा शहर भयानक अव्यवस्था का शिकार हो गया था। भराड़ी क्षेत्र में बिजली की मेन लाईन गिरने से आस – पास आग लगने तक का खतरा हो गया था। इतनी जोर की स्पार्किंग हुई की लोग घरों से बाहर निकल आये। लोगों के जानमाल को खतरा हो गया था। जब बिजली बोर्ड के जूनियर इंजिनियर को इसकी सूचना देकर मेन लाईन ऑफ करने को कहा गया तो उसका जवाब था कि ऐसा करने के उसको आदेश नही है। जेई के जवाब से स्थिति तनावपूर्ण हो गयी थी। लेकिन बोर्ड प्रशासन उस वक्त पूरी तरह हरकत में आया जब इसकी शिकायत विश्वविद्यालय के एक सेवानिवृत अधिकारी ठाकुर ने हॉलीलाज तक पहुंचा दी। इस शिकायत के बाद नालागढ़ से रातों रात लेवर मंगवाकर तीसरे दिन लाईन को सुचारू किया जा सका है। शहर में सड़को पर गिरे पेडो को काटने और उठाने के लिये भी पर्याप्त नियमित लेवर नही थी। सारी आवश्यक सेवाओं को नियमित करने के लिये ठेकेदारों के माध्यम से लेवर का प्रबन्ध संबधित विभागों को करना पडा है।

इस बर्फबारी से शीर्ष प्रशासन की असफलता खुलकर सामने आयी है क्योंकि किसी भी संबधित विभाग के पास नियमित रूप से वांच्छित लेवर है ही नही। संबधित विभागों की भूमिका सिर्फ ठेकेदारों का प्रबन्ध करने या सारी सेवाओं को आऊट सोर्स करने तक की रह गयी है इस बर्फबारी से यह झलका है कि शायद सारी सरकार ही आऊट सोर्स और ठेकेदारी के माध्यम से चल रही है क्योंकि जब प्रदेश की राजधानी में ही सामान्य जीवन ठप्प हो गया था उस समय राज्य के सचिवालय से अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर तक के लगभग सारे अधिकारी नदारद थे और प्रशासन को पूछने के लिये कोई मन्त्री तक अपने कार्यालयों में मौजूद नहीं था। बिजली मन्त्री इस पूरी त्रासदी में कहीं नजर नही आये। बल्कि मुख्यमन्त्री ने भी एक ही दिन अपनी चिन्ता जताई और उसके बाद वह भी सचिवालय से बाहर ही रहे। इस बर्फबारी में जो कुछ अनुभव यहां रहने वालों का रहा है उसका परिणाम सरकार को नगर निगम चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक में भुगतना पड़ सकता है।

# बेरोजगारी भत्ते पर वीरभद्र का स्टैण्ड पार्टी के लिये राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है

**शिमला/बलदेव शर्मा**

प्रदेश कांग्रेस ने 2012 के चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं से वायदा किया था कि सत्ता में आने पर वह उन्हें प्रतिमाह नियमित रूप से एक हजार रूपये का बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। इस वायदे से कार्यकाल के अन्तिम वर्ष में सरकार पलट गयी है। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने इस वायदे को अव्यवहारिक करार देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर परिवहन मन्त्री जीएसबाली और मुख्यमन्त्री के बीच मन्त्रीमण्डल की बैठक में अच्छी खासी तकरार भी हो चुकी है। मन्त्रीमण्डल की इस बैठक के बाद मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह और परिवहन मन्त्री जीएसबाली अलग – अलग प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी अंबिका सोनी से भेंट भी कर चुके हैं। बल्कि इस भेंट के बाद वीरभद्र सिंह ने बेरोजगारी भत्ते की मांग का विरोध और भी मुखर कर दिया है। कांगड़ा के जसूर में एक जनसभा को सबोंधित करते हुए बेरोजगारी भत्ते की अवधारणा को ही न्याय संगत मानने से इन्कार कर दिया है। दूसरी ओर अभी पंजाब विधानसभा चुनावों के लिये पूर्व प्रधान मन्त्री डा0 मनमोहन सिंह के हाथों दिल्ली में जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें बेरोजगारी भत्ता एक बहुत बड़ा वायदा बन कर सामने आया है। पंजाब के लिये चुनाव घोषणा पत्र डा0 मनमोहन सिंह के हाथों जारी किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस घोषणा पत्र को कांग्रेस हाईकमान की स्वीकृति अवश्य रही होगी। क्योंकि कांग्रेस एक क्षेत्रीय संगठन नहीं बल्कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। डा0 मनमोहन सिंह लगातार दस वर्ष तक देश के प्रधानमन्त्री रह चुके हैं और एक जाने माने अर्थ शास्त्री भी हैं। फिर यह स्वाभाविक है कि कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसी भी प्रदेश के चुनावी घोषणा पत्र में कोई भी चुनावी वायदा करते हुए यह अवश्य सुनिश्चित करेगा कि इस वायदे का राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पडेगा। प्रदेश कांग्रेस ने जब 2012 के चुनावों में बेरोजगारी भत्ते का वायदा किया था उस समय भी इसे हाईकमान की स्वीकृति रही है। इस परिदृश्य में आज चुनावी वर्ष में इस वायदे से मुख्यमन्त्री का पलटना राजनीतिक हल्कों में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है।

आज प्रदेश में प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक युवा बेरोजगारी की सुची में जुड़ रहे हैं। इन बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं। सरकार के वर्ष 2015 – 16 के आर्थिक सर्वेक्षण में दर्ज आंकड़े को यदि सही माना जाये तो वर्ष 2001 में रैगुलर सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1,39,882 थी जो कि 2015 में 1,82,049 है। जिसका अर्थ है कि 15 वर्षो में केवल करीब 42 हजार को ही रैगुलर नौकरी मिल पायी है। आर्थिक सर्वेक्षण के आकंडो के मुताबिक 2001 में पार्ट टाईम कर्मचारी थे 9,794 जो कि 2015 में 6,312 रह गये। 2001 में वर्क चार्ज 3100 थे और 2010 से शुन्य चल रहे हैं। दैनिक वेतन भोगी 2001 में 46,455 थे और 2015 में इनकी संख्या 11,552 है। इन आंकडो से स्पष्ट हो जाता है कि 15 वर्षो में कितने लोगों को सरकार में कितना रोजगार मिल पाया है। इन आंकड़ो में कान्ट्रैक्ट एडहॉक और वालंटियर के आंकडे शामिल नही है। यह आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में दर्ज हैं और विधानसभा के पटल पर रखे जा चुके हैं। इन इन आंकड़ो से स्पष्ट हो जाता है कि इन 15 वर्षो में जो भी सरकारें प्रदेश में रही हैं और उन्होने युवाओं को रोजगार देने के जो भी दावे किये हैं वास्तव में वह कितने सही रहे होगें।

इन आंकडो के आईने से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि रोजगार के क्षेत्र में सरकारों की जो भी नियत और नीति रही है उसके निष्पक्ष आकलन तथा उसको बदलने की आवश्कता हैं क्योंकि आंकड़ो की इस हकीकत को ज्यादा देर तक छिपाकर रखना संभव नही होगा। क्योंकि जब से मतदान की आयु सीमा 18 वर्ष कर दी गई है तब से 18 से 35 वर्ष के आयुवर्ग के मतदाओं की संख्या सबसे अधिक हो गयी है। संभवत: इसी हकीकत को सामने रखकर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया जा रहा है। क्योंकि इस समय कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम पर जो आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं यदि उन्हे सही भी मान लिया जाये तो भी इससे बेरोजगारी से निपटने के लिये कई दशक लग जायेंगे। ऐसे में चुनावी वर्ष में मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह का बेरोजगारी भत्ते पर लिया गया स्टैण्ड न केवल हिमाचल में ही पार्टी के लिये कठिनाई पैदा करेगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर देगा।

# राज्यपाल का उच्च मूल्यों एवं परंपराओं के संरक्षण का आग्रह

**शिमला/भारती शर्मा**

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने युवाओं से भगत सिंह, राजगुरू तथा सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों की

स्मृतियों को याद करने तथा राष्ट्र निर्माण के पथ पर चलने का आग्रह किया है।

राज्यपाल सोलन जिले के सुबाथू में 14 गोरखा प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'रन फॉर नेशन' मिनी मैराथन के अवसर पर बोल रहे थे। इस मैराथन में सुबाथू छावनी के बच्चों, युवाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

सेना की टुकड़ियों को सेना दिवस पर बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि सेना के जवान सीमावर्ती क्षेत्रों में कठिन भागौलिक परिस्थितियों में देश के लिए अपने प्राण संकट में डालकर उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करते हैं। यह उनकी निःस्वार्थ सेवाओं का परिणाम है कि हम यहां स्वतंत्रता का आनंद ले पाते हैं और शांति की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां युवाओं की ऊर्जा को सृजनात्मक तथा सकारात्मक दिशा में संचार करेती हैं और देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिये प्रेरित करती हैं।

उन्होंने कहा कि भारत एक आध्यात्मिक विचारों का देश है तथा हमारी प्रथाएं हमेशा उदार रही हैं। हमारा उद्देश्य मानव कल्याण और सेवा रहा है। उन्हाने युवाओं से अपनी समृद्ध संस्कृति, उच्च मूल्यों तथा प्रथाओं का संरक्षण करने और देश के विकास के लिए कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम स्वयं को देश के प्रति समर्पित करें और देश के लिए त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहें।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि वह समाज सुखी एवं सम्पन्न होता है, जो अपने इतिहास के महान व्यक्तियों को याद करता है। उन्होंने युवाओं से इन महान व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने युवाओं से सामाजिक जागरूकता अभियान में भी शामिल होने को कहा।

जतोग छावनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी तनु जैन ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा उन्हें आयोजन की गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की 62 छावनियों में इस तरह की मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना संचारित करना है। सांसद वीरेन्द्र कश्यप, ऑफिसियेटिड कमांडेंट, 14 जीटीसी, जतोग कर्नल एम.एस. गेनज, पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा, सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

# राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने आगजनी की घटना पर दुःख व्यक्त किया

**शिमला/रीना**

राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला जिला के विकास खण्ड चिड़गांव के तांगणू गांव में शनिवार देर रात्रि हुए भीष्म अग्निकांड पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस अग्निकांड में 30 घर पूरी तरह जल कर राख हो गए और 48 परिवार बेघर हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तथा राज्य के लोग दुःख की इस घड़ी में इन परिवारों के साथ हैं।

जिला प्रशासन ने बचाव एवं राहत कार्य शीघ्र आरम्भ किए तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तांगणू में इन परिवारों को रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। 48 परिवारों को प्रत्येक को 40 हजार रुपये की तुरंत राहत राशि प्रदान की गई है तथा भोजन, कंबल, गैस सिलेण्डर, स्टोव, तरपाल इत्यादि भी प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करवाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को तुरंत आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं।

# 556 सड़कें खोली गईं, आईपीएच की 576 योजनाएं, 97 प्रतिशत विद्युत आपूर्ति बहाल

**शिमला/भारती शर्मा**

राज्य सरकार के सरकारी तंत्र के अथक प्रयासों के चलते राज्य में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में जीवन सामान्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुल 607 प्रभावित सड़कों में से 556 को यातायात के लिए खोल दिया गया है तथा शेष 51 सड़कों को तीव्र गति खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि 12000 श्रमिकों सहित 205 जेसीबी, 28 बुलडोजर, 13 फ्रंट एण्ड लोडर्स तथा 12 रोबोटस इस बहाली कार्य के लिए तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लूहरीऔट वाया जलोड़ी पास को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। सभी सड़कें एक-दो दिन में खोल दी जाएंगी।

उन्होंने कहा कि शिमला शहर में 90 प्रतिशत बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। रामपुर तथा रोहडू में 99 प्रतिशत और जुब्बल तथा कोटखाई में 95 प्रतिशत, चौपाल में 70 प्रतिशत, भरमौर तथा तीसा में 95 प्रतिशत और सलौनी तथा डलहौजी में शत-प्रतिशत बिजली बहाल कर दी गई है। शेष क्षेत्रों में अगले दो दिनों में लोगों को बिजली मिलेगी।

728 प्रभावित योजनाओं में से 576 योजनाओं को अस्थायी तौर पर बहाल कर दिया गया है और शेष को भी अगले दो-तीन दिनों में बहाल कर दिया जाएगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को पानी की आपूर्ति उपलब्ध करवाई जा रही है।

# मानव वानर विरोधाभास पर कार्यशाला आयोजित

**शिमला/रीना**

मानव वानर विरोधाभास पर सोलन के बढोग में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। तरूण कपूर, प्रधान सचिव वन, हिमाचल प्रदेश ने समापन्न पर प्रतिभागियों तथा अन्यों को सम्बोधित करते हुये कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं क्षेत्रीय अधिकारियों को लाभप्रद होती हैं और यह हर वर्ष करनी चाहिए, जिससे समस्या के समाधान हेतु एक मंच पर विचार किए जा सकें। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि इस समस्या के सम्बन्धित समाधान का दस्तावेज तैयार किया जाए। क्योंकि कार्यशाला में अन्य राज्यों के प्रतिभागी भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि इस की कार्यशाला से हिमाचल प्रदेश वन विभाग को अन्य राज्यों के अनुभव का लाभ मिलता है तथा अन्य राज्यों को भी वन विभाग सहायता कर सकता है, उन्होंने वन्य प्राणी प्रभाग हिमाचल प्रदेशको भी निर्देश दिए कि वे इस समस्या से सम्बन्धित बिन्दुओं पर एक पुस्तिका प्रकाशित करें, जिसमें वानर पकड़ने की तकनीक भी दर्शाई गई हो।

यह कार्यशाला वन्य प्राणी प्रभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित की गई थी। देश के अन्य राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड, पंजाब, चण्डीगढ, बिहार से विशेषज्ञ व प्रतिभागी के इलावा एन.जी. ओ. तथा बर्तावि पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधार्थी ने भी भाग लिया। लगभग सौ विशेषज्ञों व प्रतिभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया। विशेषज्ञों ने जमीनी स्तर के अनुभवों को सांझा किया। कार्यशाला में वानरों के व्यवहार व उनके द्वारा नुकसान पर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा वानर नसबन्दी पर भी चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा किया जा रहे कार्यो की सराहना भी की। कार्यशाला में बताया गया कि इससे वानरों की संख्या में कमी हो रही है तथा वर्ष 2015 की गणना में यह घटकर 2,07,614 रह गई है। कार्यशाला में यह भी बताया गया कि प्रदेश में आठ नसबन्दी केन्द्रों में अभी तक 117000 वानरों की नसबन्दी की जा चुकी है।

**शैल समाचार संपादक मण्डल**

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

**HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT TENDER**
**"NOTICE INVITING TENDER"**

Sealed item rate tenders are hereby the Executive Engineer , Hamirpur Division HPPWD in form No. 6&8 on behalf of Governor of H.P. for the following works from the contractors of appropriate class enlisted with HPPWD .The tender shall be opened in the presence of the contractors/ firms of their representative who wish to be present.

Time Shedule of Tender:-

| | |
|---|---|
| 1. Date and time of receipt of application for tender form:- | 27.01.2017 upto 4:00P.M. |
| 2. Date and time of issue of tender form:- | 28.01.2017 upto 4:00 P.M. |
| 3. Date and time of receipt of tenders: | 30.01.2017 upto 10:30 A.M. |
| 4. Date and time of opening of tenders:- | 30.01.2017 at 11:00 A.M. |

The request for issue of tenders should be on the PRESCRIBED FORM Which can be obtained from the office of undersigned and tenders will be issued to only those contractors who qualify the criteria after the scrutiny of application forms by the committee constituted for this purpose.

| Sr. No. | Name of work | Estimated Cost | Earnest Money | Time Limit | Cost of form |
|---|---|---|---|---|---|
| | Construction of link road from Amroh Chowk to Jaskot Temple bifurcates from Jhaniary Neri Kamlah Baleta road ( SH:- C/O CC pavement on RD 0/200 to 0/295) (Deposit work M.P fund) | 1,88,936.00 | 3,800.00 | One Month | 350/- |
| 2. | Repair of link road to village Pankhi from Rangar Dhail road km 0/0 to 0/300. (SH:- providing and laying 2cm thick premix carpet with seal coat in RD 0/0 to 0/300 ) | 1,37,262.00 | 2800.00 | Two Months | 350/- |
| 3. | Improvement of black spot on Muthan via Khasgran raod ( SH:- C/O R/wall RD 2/015 to 2/025 with crash barrier) | 1,19,385.00 | 2400.00 | One Month | 350/- |
| 4. | Improvement of black spot on Jhaniary Neri Kamlah Baleta road km 0/0 to 9/500 ( SH:- C/O R/wall RD 5/018 to 5/030) | 1,02,441.00 | 2100.00 | One Month | 350/- |
| 5. | Improvement of black spot on Jhaniary Neri Kamlah Baleta road km 0/0 to 9/500 ( SH:- 2/950, 8/143 to 8/163 with crash barrier improvement of curves at RD 5/570 to 5/596 and 6/005 to 6/040 by cutting) | 5,06,412.00 | 10,100.00 | Two Months | 350/- |
| 6. | Improvement of black spot on Rangas Kangoo road km 0/0 to 6/0 ( SH:- Installation of crash barrier on vally side at RD 0/030 to 0/178 and C/O R/wall at RD 0/045 to 0/078) | 8,27,780.00 | 16,600.00 | Two Months | 350/- |
| 7. | Improvement of black spot on Jol Sappa road km 0/0 to 5/500 ( SH:- Excavation in hilly area in RD 4/435 to 4/540 and C/O B/Wall at RD 4/510 to 4/540) | 2,54,383.00 | 5100.00 | One Month | 350/- |
| 8. | Improvement of black spot on sujanpur Hamirpur road km 0/0 to 23/780 (SH:- C/o Retaining wall at RD 12/058 to 12/073) | 1,81,594.00 | 3700.00 | One Month | 350/- |
| 9. | Improvement of black spot installation of crash barrier and construction of retaining wall on Hamirpur Sujanpur road km 0/0 to 5/0 (SH:- Installation of crash barrier and retaining wall at RD 0/940 to 0/950) | 1,19,487.00 | 2400.00 | One Month | 350/- |
| 10. | Improvement of black spot installation of crash barrier and construction of retaining wall on Hamirpur Sujanpur road km 0/0 to 5/0 (SH:-Installation of crash barrier and retaining wall at RD 0/940 to 1/ 010 to 1/040) | 2,85,65.00 | 5700.00 | One Month | 350/- |
| 11. | Improvement of black spot on Dhaneta Hamirpur road km 18/0 to36/0(SH:-Concstruction of retaining wall at 24 /900 to 24/915) | 1,38,780.00 | 2800.00 | Two Months | 350/- |
| 12. | Improvement of black spot on Pastal Bugdhar Matroh Balduhak road (SH:-Excavation in hilly area in RD 4/075 to 4/305, 1/140 with crash barrier and R/Wall at RD 3/475 to 3/497) | 7,32,081.00 | 14,700.00 | Two Months | 350/- |
| 13. | Improvement of black spot on Dhaneta Hamirpur road km18/0 to36/0 (SH:- Coostruction of retaining 34/940 to 34/950 ) | 1,40,385.00 | 2800.00 | One Month | 350/- |
| 14. | Improvement of black spot on Dhaneta Hamirpur road km 18/0 to 36/0 (SH:-Extension of H.P Culvert at RD 29/900 (Masyana Chowk )with wing wall 29/894 to 29/899 and 29/901 to 29/906) | 143,634.00 | 2900.00 | One Months | 350/- |
| 15. | Improvement of black spot on Hamirpur Sujanpur Km0/0 24/720 (SH :- Installation of crash barrier and retaining at RD 4 /865 to 4/940 & Construction of Retaining wall at RD 4/905 to 4/925) | 4,38,0760.00 | 2800.00 | One Months. | 350/- |
| 16. | Improvement of black spot on Baroo Hamirpur via anu km 0/0 to 6/250 (SH:- Construction of Retaining wall at RD 2/210 to 2/232) | 1,61,132.00 | 3300.00 | One Month | 350/- |
| 17. | Improvement of black spot on Dhaned Lingwin Khatwin road km 0/0 to 2/200( SH:- Construction of Retaining wall at RD. 0/091 to 0/915) | 1,00,542.00 | 2000.00 | One Month | 350/- |
| 18. | Improvement of black spot on Hamirpur to anu via Brar Balh (SH:- Construction of Retaining wall at Rd 1/375 to 1/393) | 3,12,383.00 | 6300.00 | One Month | 350/- |

1. The earnest money in the shape of National Saving Certificate. Time deposit in any of the post officein HP /FDR of any Bank duly pledged in favour of Executive Engineer, Hamirpur Division HPPWD Hamirpur must be accompanied with the application for receipt of tender form along with cost of form tender application received without earnest money will summarily be rejected.
2. The contractors /firm should possess the following documents 9 photo copy to be attached application for obtaining the tenders money documents)
(i) Latest enlistment/renewal orders with application for obtaining the tenders documents.
(ii) Registration under the HP General Sales Tax Act 1968.
(iii) PAN ( Permanent Account Number)issued by the Income Tax Department.
(iv) EPF Number issued by the Compitent authority.
3. The Executive Engineer, Hamirpur Division HPPWD Hamirpur reserves the right to reject any tender without assigning any resons(s)
4. The Cess Chrges @ 1% will bee deducted from the gross amount of work done by the Contractor.
5. A contractor enlisted in a particular class shall be eligible to tender for his own class and one step below.
6. Only one No. tender form will be issued to the eligible contractor.
7. If 23.01.2017 happens to bee holiday the tender shall be opened on next working day at 11:00.

Adv. No.- 3819/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

# धर्मशाला में 57 करोड़ रुपये की विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में करीब 57 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर धर्मशाला नगर निगम के सिद्धपुर वार्ड में प्रस्तावित इंडोर खेल परिसर तथा टेनिस कोर्ट की आधारशिला रखी। इसके पश्चात् उन्होंने धर्मशाला नगर निगम की महत्वकांक्षी स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम का शिलान्यास भी किया।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने उपायुक्त परिसर में एक ही स्थल से करीब 55 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने 77.49 लाख रुपये की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सिद्धपुर स्थित आवासीय परिसर में आठ लाख रुपये के सामुदायिक भवन की आधारशिला, कनेड़ से ठम्बा तक प्रस्तावित 177.75 लाख रुपये की सड़क का शिलान्यास, 69.88 लाख रुपये की लागत से बनने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगली का शिलान्यास, 127.88 लाख रुपये की

लागत से लोअर तथा अपर चौतड़ू सड़क पर निर्मित सरगंदी नाला पुल का लोकार्पण, 1.98 करोड़ रुपये से प्रस्तावित धर्मशाला नगर के सीवरेज सिस्टम के संवर्धन तथा उदार परियोजना का शिलान्यास, राजकीय महाविद्यालय, धर्मशाला में 70.78 लाख रुपये के प्रस्तावित छात्रावास, 4.13 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के परिसर में निर्मित गोपनीयता खंड, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ही चीलगाड़ी स्थित आवासीय कॉलोनी में 1.70 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवासीय भवनों का लोकार्पण तथा पर्यटन क्षेत्र में प्रमुख मंदिरों के परिसर तथा शहरी ढांचागत उन्नयन विकास कार्यक्रम के तहत 40 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित योजना की आधारशिला रखी।

# हिमाचल में 2022 तक के किसानों की आय दुगुनी करने का टारगेट, नाबार्ड का फोकस पेपर जारी

**शिमला/जे पी भारद्वाज**

2022 तक हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय दुगुनी किस तरह से हो सकती है इसको लेकर नाबार्ड ने स्टेट फोकस पेपर तैयार कर सरकार, जनता व बैंकर्स के

सामने रख दिया हैं। नाबार्ड ने किसानों की आय कैसे बढ़ सकती हैं इसको लेकर किए अध्ययन को सरकार के समक्ष पेश किया। नाबार्ड की ओर से आयोजित राज्य कर्ज सेमीनार के मौके पर प्रदेश के मुख्य सचिव वीसी फारका ने कहा कि बदलते माहौल के हिसाब से कर्ज देने की प्राथमिकताओं में भी बदलाव की जरूरत हैं।

नाबार्ड ने 2017-18 वित वर्ष के लिए खेती, बागवानी व संबद्ध कारोबार के लिए 20332.53 करोड़ रुपए का कर्ज देने का टारगेट कर रखा हैं ये पिछले साल से 26 प्रतिशत ज्यादा हैं। इसमें से 9289.81 करोड़ रुपए खेती व इससे जुड़ी गतिविधियों को दिया जाएगा। शिक्षा के लिए 838.07 करोड़ का व मकानों को 2611.75 करोड़ रुपए कर्ज देने का टारगेट रखा गया है। सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के लिए 6308.75 करोड़ कर्ज देने का टारगेट रखा गया है।

इस मौके पर नाबार्ड के महाप्रबंधक रविंद्र कुमार ने कहा कि नाबार्ड का स्टेट फोकस पेपर बैंकर्स व जनता के ऋण और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए ब्लू-प्रिंट के रूप में काम करेगा और बैंकों की ओर से प्रदेश के लिए वार्षिक ऋण योजना बनाई जाएगी। माजूदा वित वर्ष का टारगेट पूरा न करने को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित श्रीकांत बाल्दी ने बीच में एक मिड रिव्यू बैठक करने का भी निर्देश दिया।

इस मौके पर खुलासा हुआ कि कुल 30 फीसद किसान क्रेडिट कार्ड ही आप्रेशनल है बाकियों से कोई लेनदेन नही हो रहा हैं। सरकारों की ओर से किसानों को कर्ज मुहैया कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को रामबाण बताया गया था। लेकिन हिमाचल में यह कार्ड ज्यादा काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। जबकि 80 फीसद किसान परिवारों तक ये कार्ड पहुंच चुके हैं।

नाबार्ड के डीजीएम वीके मिश्रा ने आंकड़ों का हवाला देकर खुलासा किया कि देश में केवल 15 फीसद किसान ही फसल बीमा करवा पाते है। जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ केवल 25 फीसद किसान ही ले पा रहे हैं।

इस मौके पर प्रधान सचिव कृषि व बागवानी जे सी शर्मा ने कहा कि 2022तक किसानों की आय को दुगुना करना कोई मुश्किल काम नहीं हैं। बागवानी में दस सालों में आय को तीन चार गुना तक बढ़ाया जा सकता हैं। उनके दावे कितने कागजी व कितने सही साबित होंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। चूंकि किसानों की आय को दुगुना करने के लिए कल कितना बजट लगेगा इसका कहीं कोई आकलन ही नहीं हैं और न ही ये पता है कि ये पैसा आएगा कहां से। इसके बावजूद अगर किसी प्रदेश का कृषि और बागवानी विभाग का प्रधानसचिव इस तरह के दावे करे तो उन पर संदेह तो होना ही हैं। हालांकि उन्होंने कई रास्ते भी बताए लेकिन वो धरातल पर कब आएंगे इसका किसी को पता नहीं हैं।

उन्होंने बागवानों व सिंचाई के लिए सरकार की कई सकीमें भी गिनवाई लेकिन इन स्कीमों की दशा क्या है ये सबको मालूम हैं। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने इस बात पर चिंता जताई कि बैंक दीर्घकालिक कर्ज बहुत कम दे रहे हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता हैं। इस मौके पर स्टेट फोकस पेपर का विमाचन भी किया गया।

# मौजूदा हालत से निपटने में सरकार नाकाम :अनुराग ठाकुर

**शिमला/जे पी भारद्वाज**

भारी बर्फबारी के कारण राजधानी शिमला की मौजूदा हालत में शहर और उसके आसपास के लोग पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए बुरी तरह से तरस रहे है। अनुराग ठाकुर ने मौजूदा हालत से निपटने में सरकार की नाकामी पर अपनी असहमति और नाराज़गी ज़ाहिर की।

कांग्रेस सरकार पर बुरी तरह से बरसते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस सरकार आम आदमी के हितों की रक्षा करने में बुरी तरह से नाकामयाब हुई है। राजधानी एक गंभीर समस्या से गुज़र रहा है शहर वासी पानी और बिजली की अनुपलब्धता की समस्या से खुद निपटने के लिए मजबूर हैं। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री ने बड़े-बड़े वायदे किए थे कि इस समस्या को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा, वहीं पानी और बिजली विभाग ने यह जानकारी दी है कि सप्लाई सिर्फ 13 जनवरी से ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को और लंबे वक्त के लिए परेशानी झेलनी पड़ेगी।

उन्होंने आगे कहा कि सड़क से पहुँच भी इतनी बुरी तरह से प्रभावित है कि एम्बुलेंस को मरीजों तक पहुँचने में कठिनाई आ रही है। हालाँकि, यह ध्यान में लिया जाना चाहिए कि इतनी मुश्किल परिस्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री और उनका परिवार अपनी आय से अधिक केस के बचाव के लिए दिल्ली पहुँचने में सफल हो गए। एक खास 6 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया गया था ताकि वे हेलीकाप्टर तक पहुँच सकें जो फिर उन्हें लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया।

यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारी संसाधन सीएम के भ्रष्टाचार मामलों को छिपाने के लिए बर्बाद किए जा रहे है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री अपने ही भ्रष्टाचार से जुड़े कोर्ट मामलों में व्यस्त रहेंगे, तो वे अपनी जनता की देखभाल किस तरह से करेंगे और उनके हितों की रक्षा कैसे करेंगे?

मौजूदा हालत का बुरा असर पर्यटन पर दिखाई दे रहा है। इस शहर में एक बड़ी तादाद में सैलानी बर्फबारी देखने के लिए आते हैं, लेकिन शहर की सामान्य हालत की बहाली में सरकार के बेकार प्रबंध के कारण ज्यादातर सैलानी एक कड़वा तजुर्बा लेकर वापस लौट गए हैं।

कांग्रेस सरकार झूठे वायदे, बेकार बहाने और गैर-जिम्मेदाराना रवैये से बनी हुई है और मौजूदा परिस्थिति इसी बात को साफ तौर पर दर्शाती है।''

यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि अगर राजधानी का यह हाल है तो करीब के गाँवों में हालत क्या होगी और वहाँ पर लोग कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे होंगे।

कांग्रेस सरकार का यह गैर जिम्मेदार रवैया हमेशा से बना हुआ है। जब शहर में जौंडिस फैला था, जिसके कारण हजारों लोग प्रभावित हुए थे और जिसकी वजह से कई लोगों की जानें भी गई थीं, उस वक्त सरकार ने चुप्पी साधी हुई थी और उन अपराधियों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की थी जो इस महामारी की असली वजह थे।

# समाज के प्रहरी की भूमिका निभाए मीडिया: मुख्यमंत्री

**शिमला/भारती शर्मा**

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मशाला के पूर्व छात्र संघ सभागार में फोक्स मीडिया समूह के स्वर्ण जंयती समारोह के अवसर पर आयोजन सम्मान समारोह-2017 में सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान तथा साहित्यिक सर्जन के लिए हिमाचल तथा राज्य से बाहर की 35 विभूतियों को सम्मानित किया।

वीरभद्र सिंह ने इस अवसर पर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए 100 या इससे अधिक रक्तदान करने वाले 10 व्यक्तियों तथा सामाजिक सेवा एवं साहित्यिक क्षेत्र में सर्जन के लिए 25 लोगों को सम्मानित किया गया। उन्होंने इस अवसर पर विख्यात पहाड़ी लोक गायक प्रताप शर्मा को भी सम्मानित किया। प्रताप शर्मा 'ठंड़ी-ठंड़ी हवा जे झुलदी, झुलदे चीलां दे डालू, जीणा कांगड़े दा''दो नारां, लश्कदियां तलवारां' जैसे लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पहाड़ी कवि नवीन हल्दूनवी की पुस्तक 'माहौल बिगाड़ी ता', डा. विजय पुरी की त्रैमासिक पत्रिका 'सृजन सरिता', फिरोज कुमार रोज की 'करियां निर्देशिका', आशा शैली की 'शैल सूत्र', कवि, लेखक, कलाकार तथा समीक्षक डा. सुशील हसरत नरेलवी का गजल मजमूआ तथा फोक्स हिमाचल की कृतियों का विमोचन किया।

उन्होंने इस अवसर पर चनुभान बावला की बेटियों को समर्पित 10 गुणा 160 फुट की कृति का विमोचन भी किया। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मीडिया से महात्मा गांधी तथा बाल गंगाधर तिलक जैसे महान पत्रकारों द्वारा स्थापित आदर्शों पर चलने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें स्वतंत्र, निर्भीक तथा निष्पक्ष पत्रकारिता के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया को आम आदमी तथा समाज से जुड़े मुद्दों को उठाने पर बल देना चाहिए। उन्होंने मीडिया से समाज के प्रहरी के रूप में कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही फोक्स मीडिया साप्ताहिक से दैनिक पत्र बन जाएगा। उन्होंने इस पत्र की अब तक की यात्रा पर सन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी यह इसी तरह समाज के लिए कार्य करता रहेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और अन्य समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेक पग उठाए हैं तथा पत्रकारों से सम्बन्धित विषयों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है। स्थानीय विधायक तथा शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने फोकस मीडिया समूह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में समाचार-पत्रों के विकास के माध्यम से राज्य की विकासात्मक कार्यों को भी लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है। उन्होंने फोकस मीडिया के प्रयासों की सराहना की तथा कहा कि उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे।

हिमुडा ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 21 लाख रुपये तथा कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारी संघ ने एक लाख रुपये का चौक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया।

इस दौरान आयोजित कवि गोष्ठी में राज्य तथा राज्य के बाहर के करीब 25 कवियों ने कविता पाठ किया।

उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाये.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

# क्या न्यायपालिका के भी सरोकार बदल रहे हैं

देश के पांच राज्यों में विधान सभाओं के चुनाव होने जा रहे है। इन चुनावों के परिदृश्य में यह सवाल फिर उभरा है कि जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं क्या उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति होनी चाहिए या नही? चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय इस सवाल पर विचार कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए की समय रहते ही इसका कोई जवाब जनता के सामने आ जायेगा। आज विधान सभाओं से लेकर देश की संसद तक आपराधिक मामले झेल रहे लोग जन प्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं। क्योंकि यह लोग न्यायपालिका की बजाये जनता की अदालत पर ज्यादा भरोसा करते हैं और जनता इन्हे विजयी बनाकर अपने प्रतिनिधि के रूप में आगे भेज देती है। इस जनता की अदालत में इनके आपराधिक मामलों पर कितनी बहस होती है कैसे और कौन इनका पक्ष रखता है इसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता है। केवल हार या जीत सामने आती है। इसी के कारण चुनावों में धन बल और बाहुबल के प्रभाव के आरोप लगते आ रहे हैं। यह चलन कब समाप्त होगा? कब व्यवस्थापिका को इन अपराधियों से निजात मिलेगी?

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में यह निर्देश दे रखे हैं कि जिन जन प्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामले आदलतों में लंबित हैं उनमें एक वर्ष के भीतर फैसला करना होगा। इसके लिये अगर दैनिक आधार पर भी सुनवाई करनी पड़े तो की जानी चाहिये। इसको सुनिश्चित करने के लिये अतिरिक्त अदालतें तक स्थापित करने की व्यवस्था दी गयी थी। केन्द्र सरकार ने उस समय राज्य सरकारों को इस आश्य का पत्र भी भेजा था। सर्वोच्च न्यायालय ने अधीनस्थ अदालतों को सख्त हिदायत दी थी कि एक वर्ष से अधिक का समय लगने की स्थिति में संबधित उच्च न्यायालय से इसकी अनुमति लेनी होगी। लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की अनुपालना हो पायी है? आज भी जन प्रतिनिधियों के खिलाफ वर्षो से ट्रायल में मामले लंबित हैं। क्योंकि फैसले के बाद न तो सर्वोच्च न्यायालय ने और ही सरकार ने इस बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया है। एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिये थे कि जांच ऐजैन्सी के पास आने वाली हर शिकायत पर एक सप्ताह के भीतर मामला दर्ज हो जाना चाहिये। यदि जांच अधिकरी को षिकायत पर कुछ प्रारम्भिक जांच करने की आवश्यकता लगे तो ऐसी जांच भी एक सप्ताह में पूरी करके शिकायत पर कारवाई करनी होगी। यदि जांच अधिकारी की राय में शिकायत पर मामला दर्ज करने का आधार न बनता हो तो इसकी वजह लिखित में रिकार्ड करनी होगी और शिकायतकर्ता को भी लिखित में इसकी जानकारी देनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में स्पष्ट कहा है कि किसी भी शिकायत को बिना कारवाई के नहीं समाप्त किया जायेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के इन फैसलों से उम्मीद जगी थी कि अब व्यवस्थापिका में देर सवेर आपराधिक छवि के लोगों के घुसने पर रोक लग ही जायेगी। यह भी आस बंधी थी कि पुलिस तन्त्र उसके पास आने वाली शिकायतों को आसानी से रद्दी की टोकरी में डालकर ही नहीं निपटा देगा। लगा था कि **''हर आदमी कानून के आगे बराबर है''** के वाक्य पर अमल होगा। लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमन्त्री मोदी के खिलाफ आयी प्रशान्त भूषण की शिकायत के मामले को जिस तरह से निपटाया है उससे आम आदमी की उम्मीद को गहरा आघात लगा है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमन्त्री थे उस समय उन्हें कुछ उद्योग घरानों से करीब 40 करोड़ मिलने का आरोप लगा है। इस आरोप की पुष्टि में उन्हें जो कुछ दस्तावेज मिले हैं उन पर आयकर विभाग का भी हवाला है। राहुल गांधी ने भी इन आरोपों को जनता के सामने रखा है। इन आरोपों से आज की राजनीति और आर्थिक परिस्थितियों से एक नयी बहस उठी है। क्योंकि इस समय देश में भ्रष्टाचार और कालाधन केन्द्रित मुद्दे बन चुके हैं। नोटंबदी से इस पर और भी ध्यान केन्द्रित हुआ है। राजनीतिक दल और नेता एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर हमला बोलने लगे हैं और यह एक अच्छा संकेत है। इस वस्तु स्थिति में न्यायपालिका की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच ऐजैन्सी सीबीआई को सर्वोच्च न्यायालय ही सरकार के पिंजरे का तोता करार दे चुका है। ऐसे में न्यायपालिका पर ही अन्तिम भरोसा है। यदि सर्वोच्च न्यायालय मोदी पर लगे इन आरोपों की जांच का मार्ग अपनी निगरानी में प्रशस्त कर देता तो इस भरोसे को और बल मिल जाता लेकिन इस जांच का रास्ता ही रोक दिये जाने से यह धारणा बनना और सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या बदले राजनीतिक परिदृश्य में न्यायपालिका के सरोकार भी बदल गये हैं?

# शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियां

**प्रदेश सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। राज्य ने गत चार वर्षो के दौरान राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य में 15 हजार से अधिक शिक्षण संस्थानों का एक वृहद नेटवर्क है और प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन शत – प्रतिशत है।**

वर्ष 1948 में प्रदेश में महज 52 माध्यमिक, 09 उच्च व एक महाविद्यालय था। वर्तमान में उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीनस्थ 931 उच्च, 1718 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और 116 महाविद्यालय हैं, जिसमें 06 संस्कृत महाविद्यालय, 106 स्नात्तक महाविद्यालय, 01 फाईन आर्ट कॉलेज, 01 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन तथा 01 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय धर्मशाला में संचालित है।

सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्ष 2016 – 2017 में बजट बढ़कर 6013 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2012 – 13 की तुलना में वर्ष 2016 – 17 में उच्चतर शिक्षा में बजट प्रावधान में 84.15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

शिक्षा के घर – द्वार पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2013 – 14, 2014 – 15, 2015 – 16, में 479 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत किया गया तथा 392 उच्च विद्यालयों को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत किया गया। इन विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए केवल उच्च शिक्षा विभाग में ही विभिन्न श्रेणियों के 4511 पद सृजित किए गए।

सरकार ने उच्च शिक्षा को सहजता से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2014 – 15, 2015 – 16 और 2016 – 17 में 38 नए महाविद्यालय खोले हैं और 4 महाविद्यालयों का अधिग्रहण किया गया तथा प्रत्येक महाविद्यालय के लिए प्रथम चरण में प्रति महाविद्यालय 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। इन महाविद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 1177 पद सृजित किए गए।

वर्ष 2013 – 14, 2014 – 15, 2015 – 16 और 2016 – 17 में उच्चतर शिक्षा विभाग में 3418 नियुक्तियां की गई, जिसमें 233 सहायक प्रौफेसर व 2681 पीजीटी शामिल हैं। वर्तमान सरकार ने पिछले तीन वर्षो के कार्यकाल में 9517 शिक्षकों और गैर – शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान की है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उच्चतर शिक्षा विभाग में 2609 शिक्षकों व गैर – शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया गया।

सात वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके पीटीए द्वारा उपलब्ध करवाए गए 1521 पीजीटी, 190 डीपीई और 61 सहायक प्रौफेसरों की सेवाओं को अनुबंध आधार पर लिया गया तथा 15 सहायक प्रौफेसर और 5 लिपिकों की सेवाओं का अधिग्रहण किया गया।

विद्यालयों से पठन – पाठन गतिविधियों को रोचक बनाने के लक्ष्य से शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा संचालित 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेधावी छात्र – छात्राओं को 'राजीव गांधी डिजिटल योजना' के अन्तर्गत वर्ष 2015 – 16 के 10 हजार मेधावी छात्र – छात्राओं को भी लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं, जिस पर 17,03,30,000 रुपये का व्यय किया गया है।

वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा के छात्रों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में घर से स्कूल आने तथा स्कूल से घर वापिस जाने के लिए नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। यह सुविधा वर्ष 2015 – 16 से केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी प्रदान की जा रही है।

प्रदेश के सभी वर्गो के पात्र छात्र – छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की गई हैं। इस वर्ष विभिन्न छात्रवृतियों पर 213.21 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 4,14,480 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

वर्ष 2015 – 16 में 615 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, 835 उच्च पाठशालाओं, 70 नव स्तरोन्नत वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च पाठशालाओं तथा 5 स्मार्ट स्कूलों में सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी फेज – II के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे वरिष्ठ माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षा के विषयवस्तु कम्प्यूटरों से विद्यार्थियों के उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा, जो शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाएगा।

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा गहण करने वाले 10वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को 'महात्मा गांधी वर्दी योजना' के अन्तर्गत मुफ्त वर्दियां प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2016 – 17 से कक्षा 11वीं व 12वीं के सभी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री वर्दी योजना के अनतर्गत दो सैट प्रति विद्यार्थी मुफ्त वर्दियां प्रदान करके इस वर्ष लगभग 1,78,334 छात्र – छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। गत वर्ष प्रदेश स्तर पर आयोजित विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं में चयनित 3862 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राज्य स्तर पर विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयनित 353 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2015 – 16 में प्रदेश के जिला बिलासपुर के छात्र सुरेश कुमार ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया। वर्ष 2015 – 16 में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में प्रदेश के छात्र छात्राओं ने एक स्वर्ण दो रजत और दस कांस्य पदक प्राप्त किए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंजगाई बिलासपुर के छात्र संजीत कुमार ने 74 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में तुर्की में आयोजित ओलंपिक यूथ प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करके प्रदेश को गौरवान्वित किया।

वर्ष 2015 – 16 में एन.एस.एस. योजना प्रदेश के 716 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में कार्य कर रही है। गत वर्ष इस योजना के अन्तर्गत 70532 छात्र/छात्राओं का नामांकन किया गया। इसके अतिरिक्त, एन.एस.एस. स्वयं सेवकों द्वारा विभिन्न विद्यालयों में रक्तदान शिविर, सभी विद्यालयों में स्वच्छता अभियान, योग दिवस व जागरूकता रैलियां निकाल कर समय – समय पर समाज के लोगों को जागरूक किया।

'भारत स्काउटस एवं गाईड योजना' वर्ष 2015 – 16 में प्रदेश में 1509 विद्यालयों और 38 महाविद्यालयों में कार्य कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015 – 16 में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 26035 स्काउटस (छात्र) और 20429 गाईडस (छात्र) को नामांकित किया गया है। वर्ष 2015 – 16 में प्रदेश के 206 स्काउटस और गाईडस ने राष्ट्रीय स्तर की 25 गतिविधियों में भाग लिया। गत वर्ष 153 स्काउटस को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 – 17 से 'मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना' आरम्भ करने की घोषणा की है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्यापकों को पुरस्कार स्वरूप एक वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान किया जाएगा जिनका गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयों में बोर्ड परीक्षा परिणाम पिछले पांच वर्षो में शत – प्रतिशत रहा है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आदर्श विद्यालय योजना आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 2 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को आदर्श विद्यालय नामित करके उन विद्यालयों में पठन पाठन की हर प्रकार की अत्याधुनिक तकनीक व सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

वर्तमान राज्य सरकार के सतत् व ठोस प्रयासों के फलस्वरूप ही हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

# लंबी अवधि के लिए कृषि विकास को बढ़ावा देने हेतु कदम

## भारतीय किसानों का अदम्य साहस

'गार्गी परसाई'

वर्ष 2016 में कृषि सरकार की प्राथमिकता सूची में रहा, पर वर्ष के अंत में सरकार की विमुद्रीकरण नीति के कारण यह फीका पड़ गया। गौरतलब है कि लगातार दो वर्षों का सूखा भी किसानों के अदम्य साहस को कमजोर नहीं कर पाया जिन्होंने फसल वर्ष 2015 – 16 के चौथे अग्रिम अनुमान को गलत साबित करते हुए 252.22 मिलियन टन खाद्यान का उत्पादन किया जो पिछले वर्ष 252.02 मिलियन टन के उत्पादन से कहीं ज्यादा है।

मानसून की कमी के कारण इस वर्ष देश के कुछ हिस्सों में खरीफ की फसल बर्बाद हो गई, जिससे धान, मोटे अनाज, तिलहन, दलहन और कपास के उत्पादन में मामूली गिरावट दर्ज की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने 29 दिसंबर को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हालांकि रबी में गेहूं की उपज फसल वर्ष 2015 – 16 में 93.5 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया था जो पिछले वर्ष 86.53 मिलियन टन था और प्राप्ति निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम रहा। आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने निजी अकाउंट में शून्य प्रतिशत की ड्यूटी पर गेहूं आयात की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

सरकार ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए ज्यादा से ज्यादा खाद्यान की खरीद करेगी और गेहूं उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार ने फसल वर्ष 2016 – 17 के लिए 1625 रूपया प्रति क्विंटल तय किया है, हेतु तेजी से बाजार में हस्तक्षेप भी करेगी।

इस तरीके से 2016 में कृषि के क्षेत्र में भी तेजी से डिजिटलीकरण का विकास हुआ है जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल एप की शुरूआत की गई है। कृषि मंत्रालय ने मौसम की जानकारी, बाजार की कीमतों और फसल रोगों की जानकारी देने के लिए ''किसान सुविधा''एप का शुभारंभ किया(''पूसा कृषि'' एप बीज की नई किस्मों और नवीनतम तकनीक की जानकारी उपलब्ध करा रहा है(कृषि बाजार) एप किसानों को 50 किलोमीटर के दायरे में मंडी की कीमतों के बारे में जानकारी देता है(फसल बीमा) एप फसल बीमा से संबंधित सारी जानकारी देता है(फसल को काटने संबंधित जानकारी (क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स) एप के जरिए मिलती है। लाखों किसान इन सारे एप्स को डाउनलोड कर लाभान्वित हो रहे हैं।

इस वर्ष न सिर्फ किसानों के लिए बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण देने की सीमा बढ़ाकर 9 लाख करोड़ की गई है बल्कि विमुद्रीकरण के बाद सरकार ने भुगतान के लिए कैशलेस लेन – देन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को प्रोत्साहित करने हेतु भी कई पहल की हैं। यदि ऐसा होता है तो मंडी संचालन में मीडिल मैन/कमीशन एजेंटों से किसानों को मुक्ति मिलेगी जिससे इन्हें अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने में सुविधा होगी जो इन सब किसानों के लिए बड़ा कदम होगा।

जैसा हमने देखा कि वर्ष 2016 में सरकार ने कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी, ताकि उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल से प्रभावित हो रहे क्षेत्रों जैसे मृदा स्वास्थ्य (मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया और जैविक खेती), जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से किसानों की आय के प्रभाव को कम करने के लिए (फसल बीमा योजना), निर्बाध व्यापार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच (राष्ट्रीय कृषि ई – मार्केट) तथा ज्यादा – से – ज्यादा भूमि को सिंचित खेती के तहत लाने के लिए (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) कदम उठाये गये। इसके साथ ही अन्य संबंधित क्षेत्रों जैसे दलहन, तिलहन, बागवानी, मत्स्य, पशुपालन, दुग्ध, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

वर्ष 2021 तक किसानों की आय को दोगुना करने की सरकार की प्रतिबद्धता के तहत वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लंबी अवधि के उपायों की घोषणा की है और कृषि परिव्यय जो वित्तीय वर्ष 2015 – 16 के बजट में 15809 करोड़ रूपये था उसे बढ़ाकर 39884 करोड़ रूपये किया। अंतरिम बजट में कृषि कल्याण उपकर के जरिए भी इस क्षेत्र को 5000 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी।

इसके अलावे नाबार्ड के सहयोग से 20000 करोड़ रूपये की राशि का एक अतिरिक्त कोष भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बनाया गया है जिसके तहत हर खेत को पानी देने का उद्देश्य रखा गया है। इसके तहत वर्ष 2019 तक 76.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के तहत लाया जाना प्रस्तावित है।

किसानों को मानसून के प्रभाव से बचाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने इस वर्ष से 5500 करोड़ रूपये की राशि के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत राज्य और केन्द्र सरकार मिलकर प्रीमियम की 90 प्रतिशत राशि का वहन करेंगे। इस खरीफ वर्ष में 21 राज्यों के 366.64 लाख किसानों को इसके दायरे में लाया गया है।

किसानों को उनकी उपज के विपणन और लाभकारी मूल्य प्राप्त करना सबसे बड़ा चिंता का विषय रहा है जिसके लिए सरकार ने 10 राज्यों के 250 से अधिक मंडियों को बेहतर कीमत वसूली और व्यापक पहुँच के लिए ई – एनएएन (राष्ट्रीय कृषि बाजार) पोर्टल के तहत एकीकृत किया है। पिछले सप्ताह तक इस इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म के जरिए 713.21 करोड़ रूपये का लेन – देन सम्पादित किया गया है जिसे विपणन के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

दाल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने आयात और घरेलू आपूर्ति के जरिए 2 मिलियन टन का बफर स्टॉक बनाया है। इसी समय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सरकार ने दालों के लिए ज्यादा आवंटन किया है और उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कई उपाय किए हैं। सरकार ने अगले वर्ष 20.75 मिलियन टन दाल के उत्पादन का लक्ष्य रखा है जबकि पिछले वर्ष उत्पादन 16. 47 मिलियन टन रहा था। इसके साथ ही गन्ना किसानों के बकाये का भी तेजी से भुगतान किया जा रहा है।

मानसून के प्रभाव का डर किसानों को हमेशा लगा रहता है। सरकार ने किसानों की फसलों को सूखा, बाढ़ और ओलों इत्यादि से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मुआवजे के मानदंडों में संशोधन किया है। फसल क्षति ग्रस्त होने पर किसान 33 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत मुआवजे के पात्र होंगे। पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत राज्यों को 24556 करोड़ रूपये खर्च करने के लिए दिया गया है। क्षतिग्रस्त फसलों की तस्वीरें अपलोड करने के लिए स्मार्ट फोन और इसके आकलन के लिए ड्रोन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ती जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरी हरित क्रांति पर नए उत्साह के साथ ध्यान केंद्रित किया गया है। समग्र अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इस क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि इस वर्ष कृषि की विकास दर पिछले वर्ष की तुलना में 1.1 प्रतिशत अधिक होगा।

# युवाओं को परिवर्तन की मुख्यधारा में लाना

– सुधीरेन्द्र शर्मा –

युवाओं की उद्यमी महत्वाकांक्षा और उपभोक्तावादी इच्छाओं को उनके दृष्टिकोण और विवेकपूर्ण कार्यों में नैतिकता और नैतिक मूल्यों को विकसित करने हेतु विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी देश के युवाओं को समर्पित है। आज के युवा बाजार संचालित उपभोक्तावादी संस्कृति के अत्यधिक दिखावे से सम्मोहित हैं।

वृद्धि कार्यशक्ति के जोखिम का सामना करने वाली अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारत वर्ष 2020 तक कार्य आयुवर्ग में अपनी जनसंख्या के 64 प्रतिशत के साथ देश का सबसे युवा राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। यह 'जनसांख्यिकीय लाभांश' देश के लिए एक महान अवसर प्रदान करता है। सिर्फ संख्या में ही नहीं अपितु देश की सकल राष्ट्रीय आय में भी युवा 34 प्रतिशत योगदान करते हैं।

2020 तक 28 वर्ष की औसत आयु के साथ भारत की जनसंख्या के 1. 3 बिलियन से अधिक होने की संभावना है, जो चीन और जापान की औसत आयु की तुलना में काफी कम है। चीन के (776 मिलियन) के बाद भारत की कामकाजी जनसंख्या में 2020 तक 592 मिलियन तक वृद्धि की संभावना है। यह इस तथ्य की ओर संकेत देती है कि युवा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

हालांकि एक आभासीय दुनिया से अत्यधिक घनिष्ठ रूप से जुड़े होने के कारण इस आकांक्षा वर्ग को राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में योगदान करने के लिए निर्देशों की आवश्यकता होती है। उत्पादकता सुधार में उनकी श्रम सहभागिता को बढ़ाना ही उनकी ऊर्जा को साधने का अंग होगा। चूंकि उनकी विचारधारा प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रति स्थापित हो चुकी है, इसलिये युवा शायद ही कभी अपने को इस दुनिया से परे देखते हैं।

इस तरह के पीढ़ी परिवर्तन ने पहले की किसी भी पीढ़ी से एक बेहद अलग पीढ़ी का निर्माण किया है। युवा स्वयं को स्वतंत्रता के पश्चात् की समयावधि की राष्ट्र निर्माण गाथा से दूर महसूस करते है और अपने को एक ऐसी दुनिया का प्राणी समझते है, जो आशा, प्रेम और दिव्य आशावाद के रूप में बढ़ रही है। इस प्रकार राष्ट्रीय युवा दिवस देश के लोकाचार को युवाओं से जोड़ने का एक अवसर है।

हालांकि 12 जनवरी को 1985 से प्रति वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सरकार की युवा लक्षित योजनाओं और कार्यक्रमों को राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के द्वारा निर्देशित करना है, जिसके तहत राष्ट्रों के समुदाय में अपना सही स्थान प्राप्त करने के लिए सक्षम भारत के माध्यम से उनकी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने हेतु देश के युवाओं को सशक्त बनाना है।

भारत सरकार वर्तमान में युवा लक्षित (उच्च शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल के लिए 37 हजार करोड़ रूपये) गैर लक्षित (खाद्य सब्सिडी, रोजगार के लिए 55 हजार करोड़ रूपये) के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रति वर्ष युवा विकास कार्यक्रमों पर 92 हजार करोड़ रूपये और प्रत्येक युवा पर व्यक्तिगत तौर से करीब 2710 रूपये से अधिक का निवेश करती है।

इसके अलावा राज्य सरकारें और अन्य बहुत से हितधारक युवा विकास और उत्पादक युवा भागीदारी को सक्षम बनाने की दिशा में सहायता के लिए कार्य कर रहे है, हालांकि गैर – सरकारी क्षेत्र में युवा मुद्दों पर कार्य कर रहे व्यक्तिगत संगठन छोटे और बंटे हुए हैं और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी इतिहासों में युवा परिवर्तन राष्ट्रों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर नई प्रौद्योगिकियों के सृजन में अग्रदूत रहे हैं जिन्होंने कला, संगीत और संस्कृति के नए स्वरूपों का भी सृजन किया। इसलिए युवाओं के विकास में सहायता और प्रोत्साहन सभी क्षेत्रों और हितधारकों में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।

युवा को एक कैडर के रूप में निर्मित करने की चुनौती स्वयं की छोटी सोच से परे कार्य करने और सोचने का मार्ग तय करती है। ये कार्य उन्हें उपभोग की विचारधारा से ऊपर उठने, व्यापक सांस्कृतिक विविधता की सराहना करने के लिए विचार करने और एक ऐसा बहु – आयामी परिवेश तैयार करने में मदद करती है, जहां वे सहजता से धर्म, यौन अभिविन्यास और जातियों में भेद किये बिना एक दूसरे को गले लगाने को तैयार हैं।

युवाओं को दार्शनिक दिशा – निर्देश देने के मामले में स्वामी विवेकानंद से बेहतर कौन हो सकता है, जिनके 1893 में विश्व धर्म संसद में दिए गए संभाषण ने उन्हें 'पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान का दूत' के रूप में प्रसिद्ध किया था। स्वामी विवेकनंद का मानना था कि एक देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है और इसीलिए उनकी शिक्षाएं युवाओं के विकास पर केंद्रित थी।

पिछली पीढ़ियों की तुलना में एक वैचारिक समानता से लगाव को देखते हुए देश का युवा इन शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए बेहतर स्थिति में है और वर्तमान पीढ़ी के द्वारा इन्हें आसानी से इन्हें आत्मसात किया जा सकता है। ये नई पीढ़ी एक बड़ी बाधा भी हो सकती है क्योंकि इन्होने अपने आप को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से दूर कर लिया है।

हालांकि जे वाल्टर थॉम्पसन का एक अध्ययन आशा कि किरण लेकर आता है उनके अनुसार आज का युवा ने उपभोग का दूसरा पहलु देखा है और वह बेबोन्स की तुलना में मलाला से अधिक प्रेरित है। इस पीढ़ी को नैतिक उपभोग आदतों, स्वदेशी डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग, उद्यशीलता महत्वकांक्षा और प्रगतिशील विचारों की विशेषता से चित्रित किया जा सकता है। वास्तव में उन्हें सही दिशा के लिए दार्शनिक मार्ग दर्शन की आवश्यकता है और राष्ट्रीय युवा दिवस इस मामले में युवाओं को परिवर्तन की मुख्यधारा में लाने के लिए एक सबसे उचित मंच है।

# सारे आरोप प्रमाणिक दस्तावेजों पर आधारित:धूमल

शिमला/बलदेव शर्मा

राज्पाल ने सरकार के खिलाफ आये भाजपा के आरोप पत्र को अगामी कारवाई के लिये प्रदेश सरकार के सचिवालय को भेज दिया है। सरकार इस पर क्या कारवाई करती है और क्या राज्यपाल इस पर की गयी कारवाई की रिपोर्ट सरकार से मांगते हैं या नहीं इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में ही होगा। लेकिन अभी सरकार ने इस आरोप पत्र पर प्रत्यक्षतः गंभीरता ने दिखाते हुए इसे संज्ञान लेने लायक दस्तावेज ही नही माना है। सरकार की इस प्रतिक्रिया का नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने केवल इतना जवाब दिया है कि सारे आरोप प्रमाणिक दस्तावेजों पर आधारित हैं। धूमल के अतिरिक्त भाजपा के किसी भी अन्य नेता ने इस पर कुछ नही कहा है।

इस परिदृश्य में भाजपा इस आरोप पत्र को आगे जन चर्चा में कैसे लाती है। इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में ही होगा। दूसरी ओर मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने आरोप पत्र आने से पहले ही यह चेतावनी दी थी कि यदि बेबुनियादी और प्रमाणों के बिना उन पर आरोप लगाये गये तो वह मानहानि का दावा दायर करेंगे। अब आरोप तो लग गये हैं इन पर आगे सरकार और स्वयं प्रतिपक्ष क्या रणनीति अपनाते हैं इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। इस आरोप पत्र पर जनता की प्रतिक्रिया क्या होती है इसके लिये आरोप पत्र को पाठकों के सामने यथावत रखा जा रहा है।

इस कड़ी में सरकार में हिमाचल प्रदेष के ऊर्जा व कृशि मंत्री श्री सुजान सिंह पठानिया, सुन्दरनगर के विधायक एवं मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत लखनपाल और उनके विभागों पर लगे आरोप सामने रखे जा रहे हैं।

## सुजान सिंह पठानिया के भ्रष्ट कृत्य

हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा व कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया के भ्रष्ट कृत्य भी किसी से कम नहीं हैं

**एल.ई.डी. बल्ब घोटाला :–**

घोटालों के लिए मशहूर कांग्रेस पार्टी की सरकार और इसमें एच.पी.एस.ई.बी.एल. ने नए–2 कीर्तिमान हर घर में जलने वाले एल.ई.डी. बल्ब में बड़ा घोटाला किया है। प्रदेश में कुल बिजली उपभोक्ता 22 लाख 35 हजार है, इनको प्रति उपभोक्ता तीन एल.ई.डी. बल्ब एच.पी.एस.ई.बी.एल.ने ई.ई.एस.एल. के साथ टैण्डर किया कि 7 वॉट के तीन बल्ब एल.ई.डी. के ई.एम.आई.आधार पर और 2 एल.ई.डी. बल्ब नकद भुगतान पर उपलब्ध करवायेंगे। नकद भुगतान बल्ब की कीमत 100 रू0 प्रति बल्ब।

✔ ई.एम.आई. के आधार पर बल्ब की कीमत 105 रू0।

✔ई.ई.एस.एल. ने इस कार्य के लिए आगे टैण्डर करके Discom से Agreement किया।

✔ Discom ने आगे बल्ब लेने के लिए अगला Agreement M/s CROMPTON GRIEVES LTD. (Mumbai) से किया।

✔ M/s N.T.L. Leminish India (Noida) से किया।

✔ जो एक बल्ब गरीब के घर में लगना है उसको लगाने के लिए ई.ई.एस.एल. अपना 10 प्रतिशत मुनाफा (Margine रखेगी), Discom अपना 10 प्रतिशत मुनाफा (Margine रखेगी), M/s CROMPTON GRIEVES LTD. (Mumbai) अपना 10 प्रतिशत मुनाफा (Margine रखेगी), M/s N.T.L. Leminish India (Noida) अपना 10 प्रतिशत मुनाफा रखेगी, मंत्री, अधिकारी अपना 10 प्रतिशत मुनाफा रखेंगे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त, 2016 को लाल किले से देश को सम्बोधित करते हुए एल.ई.डी. बल्ब की कीमत 50 रू0 बताई है। एच.पी.एस.ई.बी.एल. बतायें कि गरीबों के खून–पसीने की कमाई के 55 रू प्रति एल.ई.डी. बल्ब के घोटाले में कौन–2 शामिल है। इसकी पूछताछ सी.बी.आई.से पूछताछ होनी निश्चित है।

✔एल.ई.डी. बल्ब बेचने में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने डिपु होल्डरों को आदेश किए कि एल.ई.डी. बल्ब जो महंगे हैं उन्हें लो तभी आटा–चावल राशन मिलेगा।

✔ विद्युत मण्डलों के अधिकारी कर्मचारी कम्पनियों के दलाल बन कर बुला–बुलाकर उपभोक्ताओं को कहते कि बल्ब लो नहीं तो डिस्कनेक्शन हो जाएगा।

✔विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख अमर उजाला, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर ने इसमे हो रही धांधलियों को उजागर किया।

✔ बहुत बल्ब ''चाईना मेड'' हैं जबकि ऐग्रीमैंट में अपनी हिन्दुस्तानी कम्पनियों से लेने की शर्त मानी थी।

✔हजारों बल्ब बंद हो गए हैं, अब बदलने वाली कम्पनियों का कोई अता–पता नहीं है।

✔ 22 लाख 35 हजार उपभोक्ताओं को 5 बल्ब प्रति उपभोक्ता के हिसाब से 11 करोड़ 17 लाख 50 हजार बल्ब दिए जाने हैं। प्रति बल्ब 50 रू0 ज्यादा लिए जा रहे हैं। अतः कुल घोटाला 55 करोड़ 85 लाख 50 हजार का होगा।

✔ क्यों सरकार सी.एफ.एल. बल्ब की तर्ज पर मुत में प्रदेशवासियों को बल्ब उपलब्ध नहीं करवा पा ही है। यह सरकार की नालायकी है।

**✔ बिजली मीटर घोटाला :–**

जिला सिरमौर विद्युत विभाग पिछले 3–4 साल से वैंटीलेटर पर चल रहा है। जिला सिरमौर में बिजली जाना और जा कर फिर न आना, यह स्थाई रोग बन गया है। बिजली आती नहीं और बिजली के बिल बहुत जोरदार करंट मारते हैं। काला अम्ब पंचायत में नए मीटर लगाए गए, पुराने मीटर बढ़िया चल रहे थे, कोई शिकायत नहीं थी, बोर्ड द्वारा लगाए गए थे, कोई बिजली की चोरी नहीं थी परन्तु गांव वालों के मीटर बदल दिए और बदलते ही सामान्य किसान के घर का बिल 500 रू से 5000 रू, 1000 रू से 10000 रू, 1800 रू से 18000 रू आ गया। जब जनता ने अधिक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग का घेराव किया तो वह बिल घट कर आ गए। पूछा गया तो पता चला कि हिमाचल में ट्रायल के लिए कालाअम्ब पंचायत को चुना गया है और यहां पर नए मीटर लगाए गए हैं।

प्रदेश भर के मीटरों को बदलने का एक भारी भरकम घोटाला हुआ है। 22 लाख 35 हजार 158 उपभोक्ताओं के मीटर बदले जा रहे हैं, 4 लाख 38 हजार 482 मीटर बदले जा चुके हैं। जनता की जेब पर भारी मार है व सरकार मालामाल है।

**✔ बिजली बिक्री घोटाला :–**

प्रदेश में उत्पादन होने वाली बिजली की बिक्री में भारी धांधली से प्रदेश सरकार को करोड़ों रू की चपत लगाई गई है। 12–13, 13–14, 14–15 के मध्य 7401.24 मिलियन युनिट तक बिक्री की गई जिसमें से 4690.29 मिलियन युनिट बिजली पावर एक्सचेंज के माध्यम से बेची गई। जिसके दाम 3.35 रू प्रति युनिट, 2.19 रू प्रति युनिट व 3.24 रू प्रति युनिट पर बेची जबकि अन्य बिजली 3.35 रू, 3.86 रू, 3.99रू, 4.15 रू व 5.47 रू प्रति युनिट में भी बेची गई, जिसकी मात्रा नगण्य है। उक्त बेची गई बिजली की औसत 3.25 रू आई जबकि यह औसत कम से कम 4 रू प्रति युनिट आ सकती थी अर्थात् 75 पैसे प्रति युनिट का नुकसान हुआ। इसी प्रकार 2015–16 एवं 2016–17 में भी सेल की गई है। यह नुकसान अरबों रू में बैठता है। 7401 मिलियन युनिट में ही 555 करोड़ रू का नुकसान बैठता है।

**✔ कृषि विभाग में बरती जा रही अनियमितताऐं :–**

भू–संरक्षण उप–मण्डलीय अधिकारी सरकाघाट द्वारा जो टैंकों, क्रेट वर्ष के कार्य किए जा रहे हैं इनमें जो गुणवता होनी चाहिए उसको नजर अंदाज किया जा रहा हैं। उदाहरण के रूप में ग्राम पंचायत तनेड़ में जिलाधीश मण्डी द्वारा C.R.F. -2015/146, 2015/147 के अंतर्गत दी गई राशियों के लिए जाली

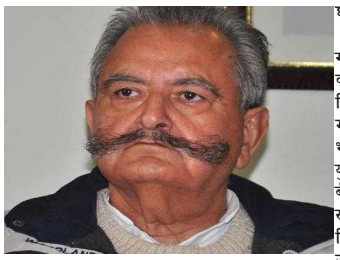

कृषि विकास संघ मेघ सिंह सुपुत्र केशव राम गांव धारड़ी डा. तनेड़ बनाया गया। कार्य के बारे जब आर.टी.आई. से सूचना मांगी तो अधिकारी और संघ के अध्यक्ष और सदस्यों ने आर.टी.आई. लेने वाले को डराया,धमकाया और गांव से बहिष्कार करने तक की धमकियां दी गई।

**आर.टी.आई. के जवाब में –**

1. खुदाई का रेट प्रति क्यूबिक मीटर–335 रू 10 पैसे
2. पत्थर की फिलिंग प्रति क्यूबिक मीटर–1029 रू 40 पैसे
3. पत्थरों की स्मंक शून्य जबकि Out of way Lead दी गई।
4. गाड़ी में HP 28–5589 Diesel –2500.00
5. सीमेन्ट की Unloading -1080 रू जबकि सीमेन्द्र इस कार्य में लगा ही नहीं।
6. नवीन पुस्तक भण्डार से सामान घर को–790 रू
7. स्टेशनरी के लिए–900रू। इसके अलावा जो जाली बिल बनाए हैं, विभिन्न दुकानों से इसकी छानबीन की जानी चाहिए।
8. जो कट स्टोन फेस स्टोन लगने चाहिए थे, नहीं लगाए गए हैं।
9. तार के जाले 1(X 1) मीटर के नहीं बनाए हैं जो मैश का साईज छोटा होना था उसमें बहुत बड़ी हेरा–फेरी है। तार विशेषकर एक ही कम्पनी से पुरानी दरों में क्रय की गई है जबकि गत् दो वर्षो से लोहे के दाम काफी कम हुए हैं।
10. मौके पर खुदाई कम की है एम.बी. में ज्यादा ली है।
11. पत्थर मौके पर थे लेकिन Lead दर्शाई गई है। ऊंची दरों में पैमैंट की गई है। इन सबको ध्यान में रखते हुए सी.बी.आई. से जांच की जाये।

✔ हिमाचल सरकार के कृषि विभाग ने किसानों के लिए Vermi Composed के लिए Tetra Poy bed बाजार की कीमतों से कई गुना ज्यादा कीमत में खरीद कर किसानो को बांटे। इनको इंस्टॉल करने तक के पैसे किसानो को नहीं दिया न इंस्टॉल करवाए, न इसका प्रशिक्षण दिया। सिर्फ औपचारिकता के लिए कुछ किसानो को बांट दिए जिसमें करोड़ों रू का घोटाला हुआ और किसी भी किसान को लाभ नहीं मिला।

**✔ नकली बीज आबंटन घोटाला :–**

प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री की शह पर ट्रेड मार्क की आड़ में पिछले 4 वर्षो से किसानों को नकली बीज बेचा गया जिसमें यु.पी.एल.कम्पनी भी दोषी है। चम्बा जिला में यु.पी.एल.कम्पनी के नकली बीजों से भरे कृषि विभाग के राजपुरा स्थित बीज भण्डार में विजिलैंस विभाग की टीम ने जुलाई, 2016 में आम किसानो की शिकायतों पर छापा मारा। मौके पर कृषि विभाग के अपने गोदाम में 10 टन से अधिक नकली कम्पनी का मटर बीच बरामद हुआ जिसका बाजारी मूल्य 20 लाख रू आंका गया है। कृषि विभाग के भण्डारण में रखा गया नकली कंपनी का बीज बरामद होने के बाद भी दोषियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही नहीं हुई। यह मामला सिर्फ चम्बा जिला का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में नकली बीजों को विभाग किसानों को आबंटित कर रहा है। नकली बीजों के आबंटन से किसानों को भारी नुकसान तो हुआ ही है, प्रदेश सरकार के कृषि विभाग को भी करोड़ों रूपये का नुकसान हुआ है।

**✔ हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड में भ्रष्टाचार का बोलबाला: –**

वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही नौणी विश्वविद्यालय के सीनियर वैज्ञानिक डा.एच.एस.बवेजा, जो वर्ष 2012 में सप्रेंड रहे, को हि.प्र. कृषि विपणन बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक बना कर प्रशासनिक अधिकारी की जगह वैज्ञानिक को बिठा नई परम्परा शुरू की। इन्होनें किसानों से जुड़े इस बोर्ड में भाई–भतीजावाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। कर्मचारी नेताओं ने इन पर अनेक बार भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के आरोप तथ्यों सहित कृषि विभाग के प्रधान सचिव, कृषि मंत्री व मुख्यमंत्री के पास लगाये परन्तु डा. बवेजा पर कारवाई होने की बजाए शिकायतकर्ता दंडित होते रहे और हि. प्र. कृषि विपणन बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बनता रहा। इन्तहा तो तब हुई जब इस भ्रष्ट अधिकारी को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कई योग्य पात्र अधिकारियों को दरकिनार कर प्रदेश के बागवानी विभाग का कार्यकारी निदेशक बना दिया।

भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि डा. बवेजा के पास मुख्यमंत्री पर चले आय से अधिक सम्पति व भ्रष्टाचार के मामले के सबूत हैं। इसी कारण मुख्यमंत्री उनको नए–2 ओहदे देकर सम्मानित करते रहते हैं।

## इंद्रदत लखनपाल की कारगुजारियां

मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत लखनपाल भोटा के विश्राम गृह में महिला मित्रों के ठहरने से चर्चा में आए थे, परन्तु उसके बाद इन्होनें अपना ध्यान सम्पतियां अर्जित करने पर केन्द्रित कर दिया। अगर इनकी प्रदेश के अंदर सम्पतियों पर नजर दौड़ायेंगे तो लगेगा कि वह सम्पतियां इनकी आय से कहीं अधिक है। शिमला जिला के तारादेवी में इनकी कोठी है, शोघी में इनका रेस्टोरेंट चल रहा है तथा हमीरपुर जिला के बड़सर में जो होटल बन रहा है, उस पर करोड़ों रू खर्च हो रहे हैं। वन भूमि पर अवैध कब्जा कर तथा सरकारी पैसे से डंगे लगाकर अपने पद का दुरूपयोग किस तरह से किया जा रहा है, यह सबके सामने है।

## सोहन लाल का भ्रष्टाचार

सुन्दरनगर के विधायक एवं मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर कीरतपुर–मनाली मार्ग निर्माण में भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। फोरलेन मार्ग निर्माण में स्थानीय विधायक ने जनता से हो रहे भेदभाव, उनकी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष उठाने में विफल रहे हैं। फोरलेन प्रभावितों ने अपनी समस्याओं को लेकर कई बार धरने, प्रदर्शन व भूख हड़ताल भी की लेकिन स्थानीय विधायक ने प्रभावितों का कभी समर्थन नहीं किया।

सी.पी.एस. ने सत्ता का दुरूपयोग कर फोरलेन कंस्ट्रक्शन कम्पनियों से सांठ–गांठ कर सुन्दरनगर के जड़ोल में अपनी जमीन पर करोड़ों रूपये के डंगे लगवाकर निजी प्लॉट तैयार करवाए। अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकारी पैसे का दुरूपयोग कर भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है।

हिमाचल प्रदेश 4 साल विकास के नाम

# मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह के गतिशील नेतृत्व में हिमाचल सरकार के चार साल उपलब्धियाँ बेमिसाल

## उद्योगीकरण से स्वावलम्बन की ओर बढ़े क़दम

- 13,262 करोड़ रुपये का निवेश
- सरकारी क्षेत्र में 44,463 रोज़गार के अवसर सृजित
- निजी क्षेत्र में 27 हज़ार से अधिक लोगों को दिया रोज़गार

- 500 करोड़ रुपये की कौशल विकास भत्ता योजना लागू, 110 करोड़ रुपये खर्च कर 1 लाख 52 हज़ार युवा लाभान्वित।
- पात्र युवाओं को 1000 रुपये और शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह भत्ता।
- कौशल विकास भत्ता सीधे लाभार्थी के खाते में जमा।
- कौशल विकास निगम स्थापित, 65000 युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित।
- प्रदेश में कौशल विकास के लिए एशियन विकास बैंक की 640 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत।

## हमारा ध्येयः रोज़गार के हों अवसर अपार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाज़ार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

# खुमली के नाम पर सिरमौर में जारी है महिला और दलित उत्पीड़न-सरकार की खामोशी सवालों में

**शिमला/शैल।**

दलित युवक से प्यार कर बैठी जिला सिरमौर की एक 21 साल की युवती का हरिद्वार में गंगा स्नान करा कर शुद्धिकरण करवाया गया व दलित युवक से अलग कर हरियाणा में उसके जबरन ब्याह को अंजाम देने का प्रयास हुआ। अगर वो घर से न भागती तो उसे या तो मार दिया जाता या फिर हरियाणा में दुल्हन बनाकर बेच दिया जाता। ये सब जिला में सदियों से चल रही 'खुमली' प्रथा के दबाव व इज्जत के नाम पर किया गया।

यही नहीं जब इस जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा मांगी तो पुलिस ने पहले इनकी शादी कराने की मंशा से इन्हें तहसीलदार के कार्यालय में घुमाया व जब तहसीलदार ने कानून का हवाला देकर शादी कराने से मना कर दिया तो पुलिस ने पंडित का इंतजाम भी किया। लेकिन इस बीच रिश्वत का दौर चला तो जो पुलिस शादी करवाने का इंतजाम कर रही थी उसी ने इन्हें रिश्तेदारों के हवाले कर दिया जो इनकी जान के प्यासे बने थे। इस तरह पुलिस ने इनकी जान को तो खतरे में डाल ही दिया।

यह झकझोरने वाला सच खुद इस 21 साल युवती ने मीडिया से साझा किया व जिले में 'खुमली' प्रथा के खिलाफ सीधे तौर पर आवाज उठा दी है। इस युवती ने सिरमौर पुलिस के कारनामों पर भी कई सनसनीखेज खुलासे किए व वीरभद्र सरकार के इस दावे की कि सिरमौर की लड़कियों को हरियाणा में दुल्हन बना कर कहीं नहीं बेचा जा रहा है के दावे की भी हवा निकाल दी हैं।

जिस तरह से हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में खापों का आतंक हैं, इस युवती की माने तो इसी तरह के कांड सिरमौर में 'खुमली' की ओर से अंजाम दिए जा रहे हैं।

अपने प्रेमी संग मीडिया से सरेआम रूबरू हुई इस युवती ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले व समाजशास्त्रियों के लिए गौर करने वाले हैं।

सुषमा शर्मा (बदला नाम) नामक इस युवती ने कहा कि नाहन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ये दलित युवक से प्रेम कर बैठी। इसकी जानकारी रिश्तेदारों को हो गई। दोनों नाहन कॉजेल में पढ़ते थे व वहीं पर अपने अपने क्वार्टर में रहते थे। सुषमा ने कहा हम पर रिश्तेदारों का दबाव बढ़ने लगा तो पुलिस में चले गए। राजगढ़ पुलिस ने दोनों को बुलाया व 13 व 14 अक्तूबर को लड़का भवान सिंह एसएचओ के घर व वह खुद कांस्टेबल नीलम के घर रही। इस बीच पुलिस ने मेरे घरवालों को फोन पर जानकारी दे दी कि ये दोनों यहां आए हैं।

15 अक्तूबर 2016 को सुषमा के रिश्तेदार गाड़ियों में आएं और लड़की को साथ ले गए। दोनों एक ही गाड़ी में बैठ गए। सुषमा ने कहा कि हमने अपने साथ पुलिस सुरक्षा की मांग की तो लक्ष्मी नारायण नामक पुलिस कर्मी को उनके साथ भेज दिया। नाहन पहुंचने पर इन दोनों को गाड़ी से उतार दिया गया व पुलिस ढाबे में बिठा दिया। सुषमा सीधा आरोप लगाती है कि उसके मामा से पुलिस ने रिश्वत ली। पुलिस कर्मी ने उनसे ये भी लिखवा लिया कि उन्हें नाहन में सुरक्षित छोड़ दिया है। अभी पुलिस वाला 15-20 कदम ही लौटा था कि लड़की के परिजनों ने जबरन लड़की को गाड़ी में ले जाने की कोशिश की। ये सब सरे बाजार हुआ व वो चिल्लाई तो पुलिस कर्मी वापस लौटा व परिजनों से कहा कि आप ऐसा सरेआम नहीं कर सकते। इस बीच मौका देखते ही दोनों लड़का व लड़की सरेआम सड़क के रास्ते भाग गए। नाहन में इन दोनों का क्वार्टर था।

**सिरमौर में लम्बे समय तक बंधुआ प्रथा रही है जिसके खिलाफ हरिजन सेवक संघ और आदिम जाति सेवक संघ सलोगड़ा के रत्न चन्द रोझे ने लम्बे समय तक संघर्ष किया है। बन्धुआ के साथ ही खुमली प्रथा के नाम पर महिला और दलित उत्पीड़न आज भी जारी है। पिछले दिनों जब सिरमौर को लेकर यह चर्चा उठी थी कि आज भी यहां महिलाओं की खरीद फरोख्त होती है और मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक जा पहुंचा था। तब मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने इस चर्चा का न केवल खण्डन ही किया था बल्कि उसके खिलाफ कड़ी आपत्ति भी जताई थी। लेकिन आज तक खुमली प्रथा के नाम पर किये जा रहे उत्पीड़न का मामला प्रदेश उच्च न्यायालय तक जा पहुंचा है और इसमें पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाये गये हैं तब पूरे तन्त्रा का इस पर मौन रहना कई और गंभीर शंकाओं को जन्म देता है। क्योंकि इस मसले पर राज्य महिला आयोग की ओर से भी अभी तक न कोई प्रतिकिया और न ही कोई कारवाई सामने आई है।**

इसके बाद ये दोनों सीधे गुनुघाट पुलिस चौकी पहुंचे और पुलिस से सारा वाक्या ब्यान किया। गुनुघाट पुलिस ने इन्हें नाहन इनके क्वार्टर छोड़ा व मकान मालिक से कहा कि अगर कोई बाहर के लोग इनसे मिलने आए तो उन्हें मिलने मत देना। पुलिस ने इन दोनों को फोन नंबर भी दिए व कहा कि अगर कोई बात हो तो तुरंत फोन करना। सुषमा ने कहा कि 15 व 16 अक्तूबर को कोई नहीं आया। 17 तारीख को चार पांच लोग आए लेकिन पुलिस को फोन किया तो ये भाग गए। ये पकड़े भी नहीं गए। इस बीच 20अक्तूबर तक कोई नहीं आया। सुषमा का आरोप है कि इस बीच रिश्तेदारों ने पुलिस से सेटिंग कर ली व 21 अक्तूबर को कई गाड़ियों में लोग आए। उन्होंने जबरन दरवाजा खोला और मेरे मुंह पर चुन्नी बांध कर मुझे अपने साथ ले गए जबकि भवान को टॉयलेट में बंद कर दिया। जब आसपास के लोगों ने पूछा कि ये क्या हो रहा है तो उन्हें कहा गया कि इसे मिरगी का दौरा पड़ा हैं। उसने कहा कि जब उसे ले जा रहे थे तो चौकी का पुलिस वाला गाड़ियों के पास खड़ा था। मुझे छुड़वाने के बजाय उनसे पूछा कि लड़का कहां हैं और मुझे जबरन ले जाने दिया। जब चार पांच घंटे के बाद किसी ने भवान की कुंडी खोली तो वो पुलिस चौकी गया लेकिन वहां पर उसे पुलिसिया रौब दिखा दिया गया।

21 को ही भवान के पिता जो कि मजदूरी करता है, के खिलाफ खुमली बिठा दी गई जिसमें कई गांवों के लोग शामिल हुए व उसे कहा गया कि अगर दोनों ने साथ रहना न छोड़ा तो समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा व लड़की को लेकर फैसला किया गया कि जिस भी लड़के को सामने लाया जाएगा लड़की को उसके साथ शादी करनी होगी।

सुषमा ने कहा कि 21 अक्तूबर के बाद पांच दिन तक उसे सतौन में रखा गया। फिर जंगल में घर था, वहां रखा गया। उसके बाद बुआ के घर रखा गया। उसने कहा कि 26 अक्तूबर को हरिद्वार में गंगा स्नान करा उसकी शुद्धि करवाई गई व पांच नवंबर को हरियाणा के किसी लड़के के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी गई। वह कहती है कि जिस लड़के के साथ उसकी शादी फिक्स की गई थी उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उससे कहा गया था कि जिस भी लड़के को लाएंगे उसके साथ शादी करनी होगी। इस बीच उसने कहा कि 2 नवबंर को वो घर से भाग गई व दो दिनों तक किसी सहेली के पास रही और सात नवंबर को दोनों किसी तरह शिमला पहुंच गई।

यहां पर दोनों अखिल भारतीय हरिजन लीग के उपाध्यक्ष केदार सिंह जिंदान से मिले व हाईकोर्ट ने दोनों को सुरक्षा देने व साथ रहने की इजाजत दे दी हैं। चूंकि लड़का अभी 21 साल का नहीं हुआ हैं तो मामला अदालत में लंबित हैं।

सुषमा कहती है कि सिरमौर में खुमली की प्रथा खत्म होनी चाहिए। वो घर से भागना नहीं चाहते थे। लेकिन खुमली परिवार पर दबाव डालती है और उसके फैसलों का मानना पड़ता हैं। उसने कहा कि सिरमौर पुलिस ने जो उनके साथ किया उसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस ने उनकी जान खतरे में डाली। उन्हें सिरमौर पुलिस पर कतई भी भरोसा नहीं हैं। उसने कहा कि सिरमौर पुलिस के अफसर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाते हैं लेकिन हम उनके पीछे नहीं पड़े रह सकते। हमें जॉब भी तो करनी हैं। सिरमौर की लड़कियों को हरियाणा में बेचा जा रहा है। प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा जेनब चदेल के ब्यान से कि वहां कुछ नहीं हो रहा हैं, सच को दरकिनार नहीं किया जा सकता। सिरमौर में महिलाओं की स्थिति दयनीय हैं। वह कहती है कि उन दोनों की जान को अभी भी खतरा बना हुआ हैं। वो पढ़ना चाहते थे लेकिन उन्हें कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा लोगों ने उनके पापा के बहुत से पैसे खर्चवा दिए है।

खुमली के फरमानों के शिकार जिंदान कहते है मामले को डीजीपी तक पहुंचा दिया गया हैं व सीआईडी जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी हुआ नहीं हैं।

# क्या अवैध कब्जों को नियमित कर पायेगी सरकार

**शिमला/शैल।**

प्रदेश की वन भूमि पर लाखें की संख्या में अवैध कब्जे हैं। इन कब्जों को नियमित करने के लिये 2002 में एक पॉलिसी बनाई गयी थी उस समय इस पॉलिसी से स्वेच्छा से ऐसे कब्जों की जानकारी मांगी गयी थी। उस समय इस पॉलिसी पर अमल हो पाने से पहले ही इसे उच्च न्यायालय में चफनौति दे दी गयी और तब से यह मामला अदालत में लंबित चल रहा है। लेकिन इसी बीच उच्च न्यायालय के संज्ञान में अवैध वन कटान के कई मामले आ गये। अदालत ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुये अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश दिये हैं। सरकारी तन्त्र को अदालत के निर्देशों पर अम्ल करने के लिये बाध्य होना पड़ा है पर अवैध कब्जे सबसे अधिक जिला शिमला में पाये गये है जिन पर सेब के बागीचे उगाा रखे हैं। अस अवैध कब्जे हटाने की कारवाई में इन बागीचों को हटाना पड़ रहा है। इससे पूरा सेब उत्पादक वर्ग प्रभावित हो रहा है और रोष में हैं सरकार का यह रोष चुनावों में मंहगा पड़ सकता है। इस संभावित चुनावी नुकसान से बचने के लिये सरकार विकल्प तलाश रही है। हाईकोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई टालने के लिए अर्जी दी गई हैं तो प्रदेश सरकार के बड़े बाबूओं को काम पर लगा रखा हैं।

वीरभद्र सिंह सरकार के राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने इस बावत सचिवालय में बड़े बाबूओं की बैठक ली व इसमें दूसरे मंत्री व कांग्रेस के विधायक भी शामिल हुए। प्रदेश सरकार ने इस मसले पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर रखी है।

ये अलग मसला है कि पिछले तीन सालों से प्रदेश में हजारों अवैध कब्जे हटा दिए गए हैं व प्रदेश हाईकोर्ट सरकार की कई अर्जियों को दरकिनार कर चुकी है। सरकार ने अब फिर कुछ नया करने का सोचा है। जबकि दूसरी ओर हाईकोर्ट में अब से एक महीने की छुटियां हो गयी है। अवैध कब्जों का मसला आगामी चुनावों में बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा हैं। इसे भांपते हुए सरकार ने कसरतें शुरू कर दी हैं। इसके अलावा चुनावों में भाजपा को भी जवाब देने का हथियार तैयार रखा जा रहा है। कांग्रेस ये कहती आ रही है कि भाजपा ने अवैध कब्जों को लेकर कुछ नहीं किया व अवैध कब्जाधारियों से शपथपत्र लेकर उनके खिलाफ बाद में मुकदमें बनवा दिए।

प्रदेश में अवैध कब्जों के मामलों की समीक्षा के लिए गठित इस उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक यहां स्वास्थ्य, राजस्व एवं कानून मंत्री कौल सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न भागों में अवैध कब्जों की नवीनतम स्थिति की समीक्षा की गई।

राजस्व मंत्री ने कहा कि हिमाचल एक कल्याणकारी राज्य है और ऐसे में लोगों की आजीविका से जुड़े अधिकारों का संरक्षण करना राज्य का दायित्व है। उन्होंने कहा कि लोगों की आजीविका तथा मानवीय संवेदनाओं के दृष्टिगत राज्य सरकार राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि सरकार बड़े अवैध कब्जाधारियों के प्रति सख्त है और दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई भी की जा रही है।

समिति ने विस्तृत चर्चा के उपरांत अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व को कानून के अनुसार सभी संभव विधिक विकल्प तलाशने व सुझाव देने को कहा है कि क्या दूरदराज क्षेत्रों से सम्बन्धित 10 बीघा से कम भूमि वाले छोटे व सीमांत किसानों को कुछ राहत प्रदान की जा सकती है।

बैठक में अवगत करवाया गया कि सरकारी भूमि पर छोटे अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध मामलों की सुनवाई स्थगित करने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दिया गया है, जो अभी लम्बित है।

क्या सरकारी भूमि पर छोटे व सीमांत किसानों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए कोई अधिनियम लाया जा सकता है, इसकी जांच एवं संभावना तलाशने का निर्णय लिया गया। सरकारी भूमि पर छोटे व सीमांत किसानों द्वारा अति आवश्यकता में किए गए अवैध कब्जों पर इन किसानों को मानवीय आधार पर राहत प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने के लिए हर संभव विधिक समाधान की संभावना का पता लगाने का भी निर्णय लिया गया।

समिति ने उच्च न्यायालय में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने से सम्बन्धित विभिन्न लम्बित याचिकाओं की सुनवाई विशेष बैंच के समक्ष एक साथ करने के बारे में आवेदन की संभावना का पता लगाने का निर्णय लिया गया ताकि अवैध कब्जे हटाने के निर्देशों में समानता बन सके।

बैठक में छोटे व सीमांत किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकारी भूमि पर हिमाचल प्रदेश अवैध कब्जों के नियमितिकरण के मामलों में, एवं सरकारी भूमि के निपटारे सम्बन्धी नियम, 2002 में यदि कोई संशोधन की संभावना हो, इसके लिए सुझाव मांगे गए। समिति की अगली बैठक 28 जनवरी को शिमला में प्रातः 11 बजे निर्धारित की गई है।